## बिड़ला-अंबानी रिपोर्ट :

# शिक्षा को बाज़ारू बनाने का दस्तावेज

बिड़ला-अंबानी टास्क फ़ोर्स ने 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका शीर्षक था 'शिक्षा में पूंजीनिवेश के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क।' पहले शिक्षा के व्यवसायीकरण से संबंधित सुझावों को अकादमिक, तकनीकी या लच्छेदार भाषा में पेश किया जाता था, जबकि इस रिपोर्ट में ऐसी कोई पर्देदारी नहीं थी। इन दोनों पूंजीपतियों ने बड़े ही साफ़-साफ़ और दो टूक शब्दों में उच्च शिक्षा को पूरी तरह बाज़ार के हवाले करने और मुनाफ़े का साधन बनाने की मांग की है।

1947 में देश के शासक वर्गों ने एक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला रखी थी। लेकिन बिड़ला और अंबानी ने उस बुनियाद की आख़िरी ईंट तक उखाड़ फेंकने ओर शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह पूंजीपतियों के सुपुर्द करने की सिफ़ारिश की है।

इस मायने में यह रिपोर्ट सभी पूर्ववर्ती रिपोर्टों के सुझावों, सलाहों और निर्देशों को एक साथ प्रस्तुत करती है और शिक्षा के निजीकरण के ठोस तरीके भी सुझाती है।

अंबानी और बिड़ला की निगाह में शिक्षा क्षेत्र एक लाभदायक बाज़ार है जिस पर पूंजीपतियों का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य 'हर नयी परिस्थिति में ढल जाने योग्य प्रतिस्पर्द्धी मज़दूरों को तैयार करना होना चाहिए, जो नये कौशल को सीखने और नये तरीके इजाद करने में निपुण हों।' इसके लिए वे जरूरी समझते हैं कि हम अपनी पहले से चली आ रही इस 'मानसिकता में बुनियादी बदलाव लायें' जिसके चलते हम 'शिक्षा को सामाजिक विकास का अंग मानते हैं।' वे इस बात पर भी नाराजगी जताते हैं कि 'भारत में शिक्षा के क्षेत्र पर संभवत: अन्य सभी क्षेत्रों से ज़्यादा सरकारी नियंत्रण है। हर चीज कायदे-कानून से संचालित होती है, चाहे जगह का चुनाव हो या छात्रों की संख्या, पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु हो या फ़ीस का ढांचा, नियुक्तियां हों या शिक्षकों को मिलने वाले मुआवज़े।' वे शिक्षा के इस 'अत्यधिक नियंत्रण' के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि यह 'निजी पूंजी लगाने वालों के मार्ग में बाधा' उत्पन्न करेगा। वे शिक्षण संस्थानों के 'संचालन की स्वतंत्रता और नये-नये बदलाव लाने के मामले में लचीलापन' चाहते हैं।

रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की गई है कि 'सरकार को चाहिए कि वह निजी क्षेत्र को शिक्षा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेऔर वह ऐसे जोखिमों की जिम्मेदारी खुद ले, जिनके कारण निजी वित्तीय संस्थायें उच्च शिक्षा के नाम पर कर्ज़ नहीं देना चाहती हैं।'

जाहिर है कि बिड़ला और अंबानी पूंजीपतियों के लिए पूरी आजादी चाहते हैं जिसमें जब चाहे नौकरी पर रखने और जब चाहे निकाल बाहर करने की आजादी भी शामिल है। दूसरी ओर, वे ऐसे किसी भी कानून के ख़िलाफ़ हैं जो छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और आम जनता के हितों की सुरक्षा करता हो। छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों के जनवादी अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए उन्होंने 'विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं के परिसरों में चलने वाली हर प्रकार की राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने' की सिफ़ारिश की है।

'भारत में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का बड़े पैमाने पर निजीकरण करने की सिफ़ारिश करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में सरकार की भूमिका केवल सुविधा प्रदान करने वाले सहायक के रूप में होनी चाहिए।' और उसकी 'प्राथमिक शिक्षा के मामले में अधिकतम और उच्च शिक्षा के मामले में न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए।'

रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश भी की गई है कि 'विज्ञान, तकनॉलजी, मैनेजमेंट, अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन और व्यापार में काम आने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए सरकार निजी विश्वविद्यालय कानून बनाये।' साथ ही इस तरह के विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए बड़े पूंजीपति घरानों को प्रोत्साहित करने का सुझाव भी दिया गया है। देशी पूंजीपतियों के लिए उच्च शिक्षा को व्यापार और मुनाफ़े का धंधा बनाने के साथ-साथ 'शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' की भी इस रिपोर्ट में वकालत की गई है और यह सुझाव दिया गया है कि 'सस्ती दरों पर उत्तम कोटि की शिक्षा के एक उचित स्थान के रूप में प्रचारित करते हुए भारत को बाज़ार में उतारा जाये।'

'जो उपभोग करे वही खर्चा उठाये' के सिद्धांत को उच्च शिक्षा पर सख़्ती से लागू करने की सिफ़ारिश करते हुए रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 'उच्च शिक्षा में पूरे खर्च की वसूली की ओर क्रमश: बढ़ा जाये और स्ववित्तपोषी निजी क्षेत्र को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।'

जिन पाठ्यक्रमों से भरपूर मुनाफ़ा कमाने की संभावना है, उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने की सिफ़ारिश की गई है जबकि प्राच्य भाषाओं, पुरातत्व, जीवाश्म विज्ञान, धर्म और दर्शन जैसे विषयों को बाज़ार और मुनाफ़े के लिए बेकार बताते हुए इन्हें सरकार के मत्थे मढ़ दिया गया है और साफ़ तौर पर यह कहा गया है कि 'सरकार उन विषयों में सक्रिय भूमिका निभाये और उनकी सहायता करे जिनके विद्वानों का बाज़ार पर कोई प्रभाव नहीं है।'

वे शिक्षा के उद्देश्य को ज्ञान-विज्ञान के प्रसार की जगह अपने मुनाफ़े की मशीन का कल-पुर्जा तैयार करने तक सीमित कर देना चाहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित सेवा क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए उनकी सिफ़ारिश है कि 'शिक्षा व्यवस्था पुराने तरह के औद्योगिक मज़दूर पैदा न करे, बल्कि ज्ञान आधारित मज़दूर पैदा करे।' शिक्षा के जरिये विद्यार्थियों को देश का स्वतंत्र और अधिकार संपन्न नागरिक बनाने के बजाय वे गैर-राजनीतिक, आज्ञाकारी और अनुशासित मज़दूर एवं कर्मचारी के रूप में तैयार करने के हिमायती हैं।

यह सुझाव दिया गया है कि 'जिस तरह वित्तीय क्षेत्र में स्टैंडर्ड एंड पुअर और क्रिसिल जैसी संस्थायें यह तय करती हैं कि बाज़ार में किस कंपनी का क्या मोल है, उसी तरह की स्वतंत्र संस्थायें भारत की सभी शिक्षण संस्थाओं - स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का पक्के तौर पर दर्जा तय करें' और इसी मूल्यांकन के आधार पर संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने या न देने का निर्णय हो। 'निर्धारित मानदंड से कम श्रेणी वाली संस्थाओं को बंद कर दिया जाय...साथ ही विभिन्न श्रेणी की संस्थाओं में फ़ीस का ढांचा भी भिन्न-भिन्न हो।'

निजी विश्वविद्यालय कानून की तरह बिड़ला-अंबानी रिपोर्ट को भी सरकार ने औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस रिपोर्ट के सभी सुझावों को मुस्तैदी से लागू किया जा रहा है।

**देश-विदेश, पुस्तिका-2 से**

# नेताओं द्वारा बधाइयों की भरमार

शहर में आजकल होर्डिंग्स की भरमार है। सड़क पर, बाज़ारों में, सेक्टरों और मोहल्लों में, जहां भी देखें, वहीं होर्डिंग्स द्वारा नेता और उनके चमचे जनता को शुभकामना संदेश दिये जा रहे हैं। लोहड़ी, मकर संक्रांति एवं नव वर्ष की बधाइयां दी जा रही हैं। सत्ताधारी दल के नेता हों या विपक्षी दल के, सभी 'बड़े' नेताओं की जीवंत तस्वीर पूरे शहर की शोभा बढ़ा रही है। बिजली के शायद ही कोई खंबे बचे हों, जिन पर छोटे-बड़े होर्डिंग्स न लगे हुए हैं। इन होर्डिंग्स पर नेताओं की बड़ी तस्वीरें तो छपी ही होती हैं, बधाई देने वाले चमचा श्रेणी के लोकल नेताओं की तस्वीर भी छपी होती है।

इस तरह से चमचों को भी लोग अच्छी तरह जान जाते हैं जो गली-गली और नुक्कड़ों पर थोक के भाव में 'चाय-पान' करने में जुटे होते हैं। वैसे चमचों को लोग़ अच्छी तरह जानते हैं। पर जब वे होर्डिंस पर नज़र आते हैं तो उनका रुतबा कुछ और बढ़ जाता है। साथ में राजनीतिक संभावनायें भी। इस तरह के होर्डिंग्स की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब चमचे सड़क किनारे अगर कोई पेड़ हो तो उसकी शाखाओं पर होर्डिंग लगा देते हैं।

हमारे देश में इतने तरह के और इतने ज़्यादा त्योहार हैं और साथ ही 'राष्ट्रीय त्योहार' भी कि नेताओं के चमचों को ऐसे होर्डिंग्स लगाने का मौका लगभग हमेशा ही मिला करता है। पर इन दिनों ऐसे बधाई और शुभकामना के संदेश इतने ज़्यादा हो गये हैं कि ग़रीबदास को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आख़िर इसका कारण क्या है? ग़रीबदास ने अपने माथे पर काफ़ी जोर डाला तो उसकी समझ में आया कि अब नगर निगम चुनाव काफ़ी नजदीक हैं। होर्डिंग्स और चुनाव में चाहे वह किसी तरह का हो, बड़ा ही गहरा रिश्ता है। अभी-अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था। तब आज जो 'बड़े नेता' हैं, वे अपने से 'बड़े नेताओं' को शुभकामनायें दे रहे थे। अब होर्डिंग्स में जिनके नाम से बधाई दी जा रही है, वे वही नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार कर ली।

इस तरह होर्डिंग्स और बैनरों के माध्यम से शुभकामना संदेश देने के कई फायदे हैं। पहला तो यही कि वे उन नेताओं की निगाह में आ जाते हैं जिसके नाम से शुभकामना और बधाई संदेश दिये गये हों। दूसरा यह कि जनता में उनकी धौंस अच्छी-खासी जमती है। इसके अलावा एक फ़ायदा यह भी है कि उनके चमचे भी पैदा होने लगते हैं। और चमचों के चमचे भी जन्म लेने की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं।

विधानसभा चुनाव में कोई जीता तो कोई हारा। ऐसे हारने वाले नेता जो अपने आप को तीसमार खां समझते हैं, नगर निगम का चुनाव लड़ना अपनी तौहीनी समझते हैं, पर जो ऑल रेडी नगर निगम के पार्षद हैं और पार्षद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ कर चारो खाने चित्त हुए थे, वे कम से कम नगर निगम में तो अपनी उपस्थिति बनाये रखना चाहते हैं। उनके लिए नगर निगम में पार्षद का चुनाव जीतना एक चुनौती से कम नहीं है। पार्षद रहते हुए काफ़ी

> ऐसे यह नियम है कि बिजली के खंबों पर और अन्य सरकारी स्थलों पर होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाये जा सकते और अगर लगाये गये तो नगर निगम से स्वीकृति लेकर उसके लिए तय भाड़ा दे कर ही लगाये जा सकते हैं, पर इसकी परवाह नगर निगम नहीं करता। करे भी क्यों?

मौज की है, न सड़कों पर ध्यान दिया, न नालियों-नाले पर, सफ़ाई व्यवस्था तो एकदम चौपट हो गई और साथ में आवारा पशुओं का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूछें मत। अगर आपके घर का दरवाजा ग़लती से खुला रह गया और आप बगल में पड़ोसी के यहां चले गये तो कुत्ता महोदय आराम से घर में प्रवेश कर रसोई घर से माल उड़ाते हैं और पेट भर जाने के बाद बाकायदा बिस्तर पर आराम फर्माने लगते हैं। ये इतने ढीठ होते हैं कि आपके द्वारा भगाये जाने के बावजूद भी भागना नहीं चाहते जब तक कि डंडे का ज़ोर नहीं दिखाया जाये। कुत्तों के आतंक के अलावा अब बंदरों का आतंक भी बढ़ गया है। ये बंदर जो संभवत: दिल्ली से भगाये जाने के बाद इस शहर में आ गये हैं, इस छत से उस छत पर छलांगे मारते रहते हैं और छत पर सूखने के लिए फैलाये गये कपड़ों को नोच-चोथ डालते हैं। इसके संबंध में भी पार्षद महोदयगण कुछ बोलना या अफ़सरों पर दबाव डालना उचित नहीं समझते। उधर नगर निगम के अफ़सरान ये दावे करते रहते हैं कि उन्होंने इतने आवारा पशुओं को पकड़ लिया, इतनी जगहों पर सड़क की मरम्मत करवा दी, पानी सप्लाई की पूरी व्यवस्था कर दी, आदि-आदि। पर ये पार्षद हैं कि अफ़सरों के झूठे दावे को चुनौती तक नहीं देते। वे अफ़सरों के 'लगुये-भगुये' बने रहते हैं ताकि उनकी अवैध कमाई का जरिया बना रहे। जाहिर है, ऐसे पार्षदों को अफ़सरान कुछ भाव देने से रहे। रह गई जनता तो उसे किसी से कुछ पूछने की आदत नहीं है तो वह इन 'जनप्रतिनिधियों' से क्या पूछे? जो व्यक्तिगत रूप में कुछ पूछना चाहते हैं, वे मंत्री महोदय से ही क्यों न पूछ लें। मंत्री महोदय से न पूछें तो एक अख़बार जो जनता के सवालों का जवाब हर पखवाड़े मुख्यमंत्री से दिलवाता है, वहां संपर्क क्यों न कर लें? इस तरह हमारे पार्षद मुफ़्त की रोटी खाने में ज़्यादा यकीन करते हैं।

एक पार्षद हैं जिनका क्षेत्र इस बार सिर्फ़ महिलाओं के लिए रिजर्व हो गया है। अब वे अपनी जगह बीवी को लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने ताबड़तोड़ पूरे वार्ड में उनकी होर्डिंस लगा दी और चूंकि अब तक वे चूल्हे-चौके में ही व्यस्त रहने वाली महिला थी जिनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं, इसलिए उनकी तस्वीर के नीचे लिखवा दिया '....... की बहू'। जाहिर है, कथित युवा नेता का यह सोचना है कि उनके बाप अथवा उनकी पहचान के आधार पर वोट मिल जायेंगे और उनकी बीवी पार्षद बन जायेगी। क्यों नहीं बनेगी? आखिर जब एक अंगूठाटेक महिला महापौर बनी हुई है तो यह बेचारी तो सिर्फ़ पार्षद ही बनना चाहती है। इन्होंने सिर्फ़ होर्डिंग्स का सहारा ही नहीं लिया, बल्कि एक वाहन पर तीनों तरफ अपनी, अपनी बीवी की और साथ में अपने बापू की तस्वीर लगवा कर उसे दिन भर अपने वार्ड में घुमवाया और राष्ट्रप्रेम के फ़िल्मी और गैरफ़िल्मी गीत लगातार गाड़ी पर बजते रहे। ग़रीबदास के आकलन के अनुसार इनके वार्ड में सबसे ज़्यादा होर्डिंग्स इन्हीं के लगे हुए हैं।

ऐसे यह नियम है कि बिजली के खंबों पर और अन्य सरकारी स्थलों पर होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाये जा सकते और अगर लगाये गये तो नगर निगम से स्वीकृति लेकर उसके लिए तय भाड़ा दे कर ही लगाये जा सकते हैं, पर इसकी परवाह नगर निगम नहीं करता। करे भी क्यों? आख़िर चुनाव तो नगर निगम के ही होने वाले हैं। फ़िर नगर निगम संभावित पार्षदों के लिए उदारता क्यों न बरते? और उसने विधानसभा चुनावों के दौरान भी इस मामले में पूरी उदारता दिखाई थी। हालत तो यह है कि व्यवसायी भी नगर निगम की संपत्ति पर अपने विज्ञापन - बैनर-पोस्टर आदि लगा देते हैं और निगम आंखें मूंदे रहता है। हां, कभी-कभार जब उसकी आंखें खुलती है तो वह विज्ञापन लगाने वाले व्यवसायियों-कंपनियों को बाजाप्ता स्वीकृति ले कर किराया देने की नोटिस जारी कर देता है। यह बात अलग है कि उसकी नोटिस पर कितना अमल हो पाता है।

**ग़रीबदास**